हरियाणा सरकार

समृद्ध हरियाणा

सुशासन से जन सेवा का

एक और वर्ष

हरियाणा
1
साल
दूरदर्शिता
पारदर्शिता
दृढ़-संकल्प का

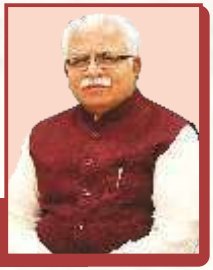

संदेश

आपकी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा हो रहा है। प्रदेश की जनता ने जिन उम्मीदों, आशाओं और विश्वास के साथ हमें पुनः जनादेश दिया था, हम उसके अनुरूप काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बदलते समय की मांग के अनुरूप हमने जनहित में कई नई पहल की हैं। इसमें मुख्य रूप से 'परिवार पहचान-पत्र' हमारे उस संकल्प को पूरा करने का आधार और मील का पत्थर है, जो हमने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए विधानसभा चुनावों के दौरान लिया था। हमारा संकल्प है कि -'हर व्यक्ति को घर तक और घर पर ही सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुँचे'। इसी प्रकार गांवों को लाल डोरा मुक्त कर ग्रामीणों को उनका मालिकाना हक प्रदान करना इसी कड़ी में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर भी 'स्वामित्व योजना' के रूप में अपनाया जा चुका है। 'ग्राम दर्शन पोर्टल' तथा कई अन्य 'ई-सेवाओं' की शुरुआत भी 'सुशासन वर्ष-2020' की अविस्मरणीय पहल है और हमारे सुशासन के संकल्प को दर्शाती है। हमने किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों आदि हर वर्ग के लिए अनेक नये कदम उठाए हैं तथा पहले से चली आ रही योजनाओं को और भी अधिक कारगर ढंग से लागू किया है।

गत एक साल की अवधि में कोविड-19 महामारी न केवल हमारे लिए बल्कि मानवमात्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। सभी प्रदेशवासियों ने बड़े साहस और धैर्य के साथ इसका डटकर मुकाबला किया है। मैं उन सभी लोगों और नागरिक संस्थाओं का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने संकट की इस घड़ी में सरकार का हर कदम पर साथ दिया और ज़रूरतमंदों की मदद की। हम सबको आगे भी मिलकर इस संघर्ष को इसी हौसले के साथ जारी रखना है और इसके साथ ही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को पूरी गति से आगे बढ़ाना है। मैं हरियाणा के हर एक नागरिक को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी खजाने के हर एक पैसे का लाभ हम उस व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं, जिसके लिए वह निर्धारित किया गया है और जिसकी भलाई और विकास में उसे लगना चाहिए।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

कैबिनेट मंत्री

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री

श्री दुष्यंत चौटाला
उप मुख्यमंत्री

कमरा नं. 40/5, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740212

श्री अनिल विज
गृह मंत्री

कमरा नं. 32/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740793

श्री कंवर पाल
शिक्षा मंत्री

कमरा नं. 34/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740010

श्री मूलचंद शर्मा
परिवहन मंत्री

कमरा नं. 49/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740157

श्री रंजीत सिंह
विद्युत मंत्री

कमरा नं. 39/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740231

श्री जय प्रकाश दलाल
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

कमरा नं. 42/6, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2743709

डॉ. बनवारी लाल
अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री

कमरा नं. 24/8, सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740906

राज्य मंत्री

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री

श्री ओम प्रकाश यादव
सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 43 सी/8 सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740867

श्रीमती कमलेश ढांडा
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री,
स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 31/8 सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740358

श्री अनूप धानक
पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री,
स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 47/8 सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740195

श्री संदीप सिह
खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री,
स्वतंत्र प्रभार

कमरा नं. 30/9 सचिवालय
दूरभाष नं. 0172–2740892

अनुक्रमांक

किसान कल्याण

हमारा लक्ष्य : किसानों की आय दोगुणी	01
हर दाने की खरीद के लिए प्रतिबद्ध सरकार	03
मंडियों में सरकारी खरीद पर रियायतें व सुविधाएं	05
दूरदर्शी सोच : प्रगतिशील किसान	07
बागवानी से समृद्धि	09
हमारा संकल्प - बूंद-बूंद बचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे	11
पशुपालन व मत्स्य पालन बना अब आय का एक और साधन	13

शिक्षा

नई शिक्षा - बेहतर भविष्य	15

स्वास्थ्य

स्वस्थ हरियाणा - सशक्त हरियाणा 19

खेल एवं योग - काया रहे निरोग 23

हरा-भरा हरियाणा - स्वस्थ हरियाणा 25

सुरक्षा

सबकी सुरक्षा - हमारा संकल्प 27

स्वावलम्बन

कौशल से संवरता भविष्य, सक्षम युवा - सशक्त युवा 29

सम्मान

सबका सम्मान - सबका उत्थान 31

हर समस्या का निदान, कर्मचारियों का भी पूरा सम्मान 33

सुशासन

ई - गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस 35

ग्रामीण विकास

ग्रामीण क्षेत्र की बदलती तस्वीर 37

शहरी विकास

शहरों का कायाकल्प 39

सबको आवास 41

बिजली

बिजली का प्रसार - विकास का आधार 43

सौर ऊर्जा से बिजली की बचत 45

उभरते उद्योग व व्यापार

प्रगति की रफ्तार - उद्योग व व्यापार 47

व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं 49

सुगम परिवहन

सड़क हुई सुदृढ़, रेल से मिली रफ्तार 51

सुरक्षित व सुगम सफर 53

पेयजल व सीवरेज व्यवस्था

हमारा ध्येय : हर घर पहुंचे स्वच्छ जल 55

कोविड-19 महामारी

कोविड-19 महामारी के दौरान राहत 57

इलाज के लिए प्रबन्ध 59

किसान कल्याण

हमारा लक्ष्य : किसानों की आय दोगुणी

- 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के तहत प्रदेश के 17.64 लाख लघु और सीमांत किसानों के खातों में दी 1816.51 करोड़ रुपये की राशि।
- 'एकमुश्त निपटान योजना' में 3.08 लाख किसानों की 1001.72 करोड़ रुपये की ब्याज व जुर्माना राशि माफ।

- 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत गत 6 वर्षों में 12,80,545 किसानों को 2943 करोड़ 92 लाख 86 हज़ार रुपये की राशि क्लेम के रूप में दी, जबकि किसानों ने 913.93 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया।

- 'नलकूप बिजली बिल जुर्माना माफी योजना' के तहत 1.12 लाख किसानों का 23.93 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ।

- किसानों को सस्ती दरों पर बिजली आपूर्ति करने के लिए वर्ष 2020-21 में 6040 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी का प्रावधान।

- 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना' के तहत कोविड-19 के कारण होने वाली मृत्यु को ध्यान में रखते हुए मुआवज़े की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया।

- आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 3870 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित, जिसके तहत उपकरणों के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान।

- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कृषि क्षेत्र का बजट 5474.25 करोड़ रुपये निर्धारित किया।

- बैंकों से किसानों के लेन-देन पर लगने वाली स्टांप फीस 2000 रुपये से घटाकर 100 रुपये की।

किसान कल्याण

हर दाने की खरीद के लिए प्रतिबद्ध सरकार

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।

- रबी सीज़न 2020-21 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाकर 1975 रुपये, जौ का 1600 रुपये, चने व मसूर का 5100 रुपये तथा सरसों का 4650 रुपये प्रति क्विंटल किया।
- धान खरीद की प्रति एकड़ निर्धारित मात्रा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 30 क्विंटल प्रति एकड़ की। यदि किसान 10 प्रतिशत अतिरिक्त धान मंडी में लेकर आता है, तो उसे भी खरीदने का प्रावधान।
- गन्ने का भाव बढ़ाकर 350 रुपये प्रति क्विंटल तक किया, जो पूरे देश में सर्वाधिक।
- गेहूं, धान, सूरजमुखी, मूंग, सरसों, चना, बाजरा इत्यादि फसलों के हर दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है और खरीद का भुगतान तीन दिनों में सीधे किसानों के खातों में करने का प्रावधान।
- हरियाणा के इतिहास में पहली बार रबी सीज़न 2019-2020 की फसलों की सरकारी खरीद पर 8 लाख से भी अधिक किसानों के खातों में 17 हज़ार करोड़ रुपये की राशि सीधे डाली गई।

किसान कल्याण

मंडियों में सरकारी खरीद पर रियायतें व सुविधाएं

- फसलों की सुगम खरीद, मुआवज़ा, आर्थिक सहायता व योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल शुरू। इस पोर्टल पर रबी सीज़न 2019-20 में 10.32 लाख किसानों ने 64.67 लाख हेक्टेयर भूमि का और खरीफ सीज़न 2020 में 8.78 लाख किसानों ने 48.72 लाख हेक्टेयर भूमि का पंजीकरण करवाया।

- खरीफ सीज़न 2020 में इस पोर्टल पर बाजरे की फसल के लिए 3,10,550 किसानों ने 12,26,460 एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया।
- मंडियों में किसानों व मज़दूरों के लिए 10 रुपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 'अटल किसान मज़दूर कैंटीन' योजना के तहत 12 ज़िलों में कैंटीन शुरू व 13 कैंटीन जल्द होंगी शुरू।
- गुरुग्राम में 8 एकड़ भूमि पर फूलों की मंडी तथा पिंजौर में एच.एम.टी. की खाली पड़ी 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल व सब्जी मंडी निर्माणाधीन।
- खरीद बंद होने पर आढ़ती की दामी व लेबर की पेमेंट 15 दिन के भीतर करने का प्रावधान। इस अवधि में पेमेंट न होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का प्रावधान।
- मंडियों में किसानों और आढ़तियों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर।
- कपास और धान पर मार्केट फीस व ग्रामीण शुल्क 2 प्रतिशत से कम करके आधा प्रतिशत किया।
- 3 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त फसली ऋण की सुविधा सहकारी एवं राष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से भी उपलब्ध करवाने का निर्णय। पहले यह सुविधा केवल 1.50 लाख रुपये तक उपलब्ध थी।

दूरदर्शी सोच : प्रगतिशील किसान

- 'प्रगतिशील किसान सम्मान योजना' के तहत प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपये, द्वितीय स्थान के लिए 2 किसानों को 3-3 लाख रुपये, तृतीय स्थान के लिए 5 किसानों को 1-1 लाख रुपये तथा 100 किसानों को 50-50 हज़ार रुपये के सांत्वना पुरस्कार।

- 'प्रगतिशील किसान ट्रेनर' योजना के तहत प्रगतिशील किसान आसपास के कम से कम 10 किसानों को सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रणालियां अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
- 'किसान मित्र योजना' के तहत प्रगतिशील किसान 'किसान मित्र' के रूप में काम करेगा और एक किसान मित्र 100 किसानों की वित्तीय प्रबंधन में मदद करेगा। इस योजना में 17 हज़ार 'किसान मित्र' 17 लाख किसानों का मार्गदर्शन करेंगे।
- प्रदेश में 'हरित स्टोर' के नाम से 2000 'रिटेल आउटलेट' खोलने का निर्णय, जो मिनी सुपर मार्केट के रूप में कार्य करेंगे। इन पर सहकारी उत्पादों के साथ 'स्वयं सहायता समूहों' के उत्पाद भी बेचे जाएंगे।
- राज्य में 192 नई मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।
- 'ईखशु शुगर' नाम से रिफाइंड शुगर ब्रांड की छोटी पेकिंग्स शुरू, जिसकी कीमत 38 रुपये प्रति किलोग्राम।

किसान कल्याण

बागवानी से समृद्धि

- 'भावान्तर भरपाई योजना' में 19 बागवानी फसलें शामिल। इसमें टमाटर, प्याज, आलू व फूलगोभी की फसल के अतिरिक्त 15 अन्य फसलें- किन्नू, अमरूद, गाजर, मटर, शिमला मिर्च,

बैंगन, भिंडी, हरी मिर्च, लौकी, करेला, बंदगोभी, मूली, अदरक, हल्दी व आम इत्यादि भी शामिल की गईं।

- प्रदेश में बागवानी-क्षेत्र बढ़कर 5.26 लाख हेक्टेयर हुआ, जो कुल क्षेत्र का 7.07 प्रतिशत है।

- बागवानी फसलों की सुगम बिक्री व उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 486 FPO बनाए जा चुके हैं तथा 514 और बनाने का लक्ष्य है। इनके द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पैक हाउस बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान अपनी फसल व सब्जियां सरलता से बेच सकेंगे।

हमारा संकल्प–बूंद–बूंद बचाएंगे, हर खेत तक पानी पहुँचाएंगे

- प्रदेश में धान की जगह कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना के तहत किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान। इस पोर्टल पर 1,26,910 हेक्टेयर में धान की जगह अन्य फसलों को उगाने के लिए पंजीकरण।

- 'भूमिगत पाइप लाइन स्कीम' के तहत किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ या अधिकतम 60,000 रुपये प्रति किसान अनुदान राशि।
- 'फव्वारा संयंत्र प्रणाली' से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई। इसमें किसानों को 85 प्रतिशत सब्सिडी।
- 'अटल भूजल योजना' के तहत पांच वर्षों में कुल 723.19 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्रावधान। इसमें अत्यधिक भूजल दोहन व निरन्तर घटते भूजल स्तर वाले 13 ज़िलों के 36 ब्लॉकों की 1895 ग्राम पंचायतों का 12.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल कवर किया जाएगा।
- 'हरियाणा राज्य तालाब विकास प्राधिकरण' द्वारा गंदे पानी वाले तालाबों का जीर्णोद्धार करने की योजना के तहत 200 तालाबों पर काम शुरू।

किसान कल्याण

पशुपालन व मत्स्य पालन बना आय का अब एक और साधन

- 'पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड' योजना की शुरुआत। इस क्रेडिट कार्ड की सीमा 1.60 लाख रुपये है। इसके तहत अब तक 6 लाख पशुपालकों का पंजीकरण तथा 51,156 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड दिये।

- दुधारू पशुओं की खरीद हेतु बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा के तहत 1692 डेयरी इकाइयां स्थापित।
- 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना' के अन्तर्गत 3.31 लाख पशुओं का बीमा किया।
- दूध उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता बढ़कर 1142 ग्राम हुई।
- प्रदेश अब पशुओं के मुंहखुर व गलघोंटू जैसे रोगों से मुक्त। एक वर्ष में 75.30 लाख पशुओं का टीकाकरण।
- 'राष्ट्रीय पशु गर्भाधान कार्यक्रम' के तहत 1.15 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया।
- 17,216 हेक्टेयर जलक्षेत्र में मत्स्य पालन। 22,500 मत्स्य पालकों द्वारा 8232 पंचायती तथा 2100 निजी तालाबों में मछली उत्पादन।
- 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के तहत 1400 मछुआरों व मत्स्य पालकों का 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क बीमा।

नई शिक्षा – बेहतर भविष्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 की सिफारिशें लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य।
- नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक लड़कियों का उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक करने का लक्ष्य। कक्षा 9वीं से 12वीं के सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान।

- धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए **सुपर-100 कार्यक्रम** के तहत रेवाड़ी और पंचकूला में सरकारी विद्यालयों के बच्चों के लिए रहने, खाने व स्टेशनरी के मुफ्त सुविधायुक्त कोचिंग सेंटर्स खोले गए। इनके 25 छात्रों का आई.आई.टी. और 72 विद्यार्थियों का नीट में चयन। दो और कोचिंग सेंटर खोलने का निर्णय।

- बच्चों के लिए 4000 प्ले-वे स्कूल खोलने का निर्णय, जिनमें से 1135 पर काम शुरू।

- प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधा और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने के लिए 112 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय।

- कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने 6 सैनेटरी पैड का पैकेट मुफ्त देने का निर्णय। इससे लगभग 7 लाख छात्राएं लाभान्वित।

- विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था। NCERT द्वारा टी.वी. चैनलों के माध्यम से 52 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा। रिकार्डिड लेक्चर भी टी.वी. चैनलों व केबल नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध।

- 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए 'छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना' के तहत मुफ्त परिवहन सुविधा।

- बच्चों और अभिभावकों की टेली-काउंसलिंग (भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं) के लिए 16 उम्मीद केंद्र खोले। इनमें 2,06,150 विद्यार्थियों व अभिभावकों को परामर्श दिया तथा 1610 विद्यार्थियों व अभिभावकों की काउंसलिंग की।

शिक्षा

नई शिक्षा – बेहतर भविष्य

- 'हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा' (एचटेट) की मान्यता 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की।
- एचटेट परीक्षा के लिए परिक्षार्थियों के निवास स्थान से 50 किलोमीटर से बाहर कोई केन्द्र नहीं दिया जाएगा।

- एक वर्ष में लड़कियों के लिए 15 नए सरकारी कॉलेज खोले गए। गत छः वर्षों में कुल 67 नये राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 42 लड़कियों के हैं।
- विदेशों में उच्च शिक्षा तथा रोज़गार के लिए महाविद्यालयों में ही पासपोर्ट बनवाने की सुविधा के तहत 6,538 आवेदन प्राप्त।
- होडल (पलवल) में 22 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय महाविद्यालय तथा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, हिसार में 16.56 करोड़ रुपये की लागत से टीचिंग ब्लॉक व कन्या छात्रावास निर्मित।
- राजकीय स्कूलों के 1.87 लाख छात्रों के लिए शिक्षकों ने उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपने लेक्चर अपलोड किए ताकि छात्र घर पर ही शिक्षा सेतु एप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- एजुसेट पर भी कक्षाएं लगाई गईं। 'मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम' के तहत 52 लाख स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए 'रिलायंस जियो टी.वी.' के साथ समझौता। इसके तहत एजुसेट के चारों चैनल जियो के प्लेटफार्म पर निःशुल्क उपलब्ध।
- विद्यार्थियों की शंकाओं और सवालों के समाधान हेतु Whatsapp, Google Suite बनाया गया।
- प्राइमरी स्कूलों के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए 'संपर्क बैठक' ऑफलाइन मोबाइल एप शुरू की गई।

स्वस्थ हरियाणा – सशक्त हरियाणा

- गरीब व ज़रूरतमंद परिवारों को 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत 5 लाख रुपये तक का सालाना मुफ्त इलाज। अब तक 22 लाख गोल्डन कार्ड बनाए व 1.74 लाख रोगियों का 150 करोड़ रुपये से मुफ्त इलाज। इस योजना में कोरोना रोगियों को भी किया शामिल।
- एनीमिया मुक्त भारत अभियान में **हरियाणा देश में प्रथम।**

- सरकारी अस्पतालों में डेंगू के रोगियों के लिए निःशुल्क सिंगल डोनर प्लेटलेट्स की नई पहल शुरू करने वाला **हरियाणा उत्तर भारत का पहला राज्य।**
- हरियाणा देश का पहला राज्य, जहां हैपेटाईटिस-सी व बी की दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध।
- सरकारी अस्पतालों में लगभग 500 तरह की दवाइयां, 228 सर्जरी, 70 प्रकार की जांचें तथा 21 प्रकार की दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं के ऑपरेशन मुफ्त।
- लोगों को घर पर ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए 'ई-संजीवनी ओ.पी.डी.' की शुरुआत। इसमें डॉक्टर रोगी को लैब टेस्ट या दवाइयों की पर्ची भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा, जो चिकित्सा के लिए हरियाणा की सभी अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्य होंगी।
- 408 एंबुलेंस हर समय उपलब्ध, 232 और एंबुलेंस खरीदने का ऑर्डर दिया, जिनमें 27 एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबुलेंस शामिल हैं।
- घर-द्वार पर ही इलाज करने के लिए राज्य में 12 मेडिकल मोबाइल यूनिट चल रही हैं तथा 47 मेडिकल मोबाइल यूनिट खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है।
- कोरियावास (महेन्द्रगढ़) में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन तथा जींद में 664 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति। इसके अतिरिक्त भिवानी और गुरुग्राम में भी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।
- हैबतपुर, जिला जींद में 663 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोला जा रहा है।
- फरीदाबाद में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है।
- सिरसा, यमुनानगर तथा कैथल में भी 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी।

स्वस्थ हरियाणा – सशक्त हरियाणा

- गांव कुटेल (करनाल) में पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कार्य प्रगति पर।
- शहीद हसन खान मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज नल्हड़, जिला नूंह में 5 एकड़ भूमि पर 135 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से डेंटल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू।

- सफीदों, जिला जींद में नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय, जिसमें ए.एन.एम व जी.एन.एम और बी.एस.सी. नर्सिंग की 60-60 सीटें होंगी।
- कैथल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकूला में एक-एक व फरीदाबाद में 2 नर्सिंग कॉलेज लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन।
- चैनत (हिसार) व ऊन (चरखी दादरी) में नए आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए।
- गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकूला व करनाल में प्लाज्मा बैंक खोले गए।
- अम्बाला कैंट, रेवाड़ी व पानीपत के नागरिक अस्पतालों को 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तरों का किया गया।
- गांव मूनक (करनाल) व खाम्बी (पलवल) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नारायणा (करनाल) व कोयल (जींद) में नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये।
- मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ई.डब्ल्यू.एस. के प्रार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण।
- 954 नए डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर नियुक्त तथा 206 आयुष वॉलिन्टियर्स डॉक्टरों की अनुबन्ध पर नियुक्ति।
- पंचकूला के सेक्टर-3 में 22 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की पहली संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब खोलने की स्वीकृति।
- गुरुग्राम में 6.20 करोड़ रुपये की लागत से श्री माता शीतला देवी स्वर्ण जयंती डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 6533.75 करोड़ रुपये निर्धारित।

खेल एवं योग – काया रहे निरोग

- हरियाणा करेगा **'खेलो इंडिया – 2021'** की मेजबानी।
- ओलम्पिक एवं पैरालम्पिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही खिलाड़ी को तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि एडवांस देने का निर्णय।

- 'लघु खेल केन्द्र योजना' के तहत मैदानों के रख-रखाव, खेल उपकरण व खेल किट आदि के लिए खेल केन्द्रों को एकमुश्त पांच लाख रुपये की राशि देने का प्रावधान।
- प्रदेश के 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं खोलने का लक्ष्य। 511 व्यायामशालाएं शुरू और लगभग 600 का काम हुआ पूरा व 26 खेल स्टेडियम निर्माणाधीन।
- विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले प्रदेश के पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपये नकद सहित ग्रेड-'सी' स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट।
- राज्य स्तरीय स्कूली खिलाड़ियों की डाइट राशि 125 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिदिन तथा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की डाइट राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन की।
- योग को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायक एवं 22 आयुष कोच के पद स्वीकृत।

हरा-भरा हरियाणा - स्वस्थ हरियाणा

- इस साल पराली प्रबंधन के लिए 216.21 करोड़ रुपये की राशि मंजूर।
- फसल अवशेष जलाने से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन' के उपकरणों पर किसान को 50 प्रतिशत तथा कस्टम हायरिंग सेंटर्स को 80 प्रतिशत अनुदान।

- पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए पराली की गांठ बनाने पर 1000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान।
- रेड ज़ोन क्षेत्र में स्थित गांव में पराली न जलाने पर पंचायत को 10 लाख रुपये तक नकद पुरस्कार।
- सरकार के प्रयासों से पराली जलाने के मामलों में आई 60-70 प्रतिशत तक की कमी।
- पराली का उपयोग बिजली बनाने में करने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद एवं जींद में 49.08 मेगावाट क्षमता की बायोमास परियोजनाएं स्वीकृत। कुरुक्षेत्र व कैथल की परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर।
- 1126 गांवों का हरा-भरा करने के लिए चयन। प्रत्येक गांव के एक युवा को वृक्ष मित्र लगाया।
- वर्ष 2020-21 में 1.27 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। अब तक 84.33 लाख पौधे लगाए।
- 'पौधागिरी योजना' के तहत वर्ष 2020-21 में 8.88 लाख पौधे स्कूली विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए।
- 'जल-शक्ति अभियान' के तहत वर्ष 2020-21 में अब तब 67.91 लाख क्लोनल सफेदा के पौधे लगाए।
- शहरी वानिकी के तहत सभी शहरों में 59,500 बड़े पौधे लगाये गये।
- साढौरा (यमुनानगर) में 7.05 एकड़ भूमि पर नगर वन विकसित। मुकारमपुर तथा ताजकपुर में 12.05 एकड़ जमीन पर भी नगरीय वन विकसित करने की योजना।

सबकी सुरक्षा – हमारा संकल्प

- किसी भी संकट अथवा आपातकालीन स्थिति में मदद पाने के लिए डायल 112 सेवा जल्द ही शुरू की जा रही है। इसके लिए 630 नई पीसीआर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं।
- सबूत से छेड़छाड़ की आशंका खत्म करने के लिए पुलिस कॉम्पलैक्स, मधुबन स्थित फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में 'ट्रैकिया' बार-कोडिंग सिस्टम शुरू।

- पांच पुलिस रेंज मुख्यालय और कमिश्नरेट, फरीदाबाद में कुल 6 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने की स्वीकृति तथा प्रदेश में 15 नए पुलिस थाने खोले।
- गत एक साल में 59 निरीक्षकों को पदोन्नत करके तथा 7 अन्य पदों पर सीधे भर्ती से डी.एस.पी. लगाए गए।
- वर्ष 2014 में पुलिस बल में बेटियों की संख्या मात्र 3 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया। अब लक्ष्य 15 प्रतिशत करने का है।
- गुलाबी रंग की 150 महिला बसें चलाईं, जिनमें सी.सी.टी.वी. व जी.पी.एस. लगे हैं। इसी तरह 300 सामान्य बसों में और 105 बस अड्डों पर भी सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गये।
- 'छात्रा सुरक्षित परिवहन योजना' के तहत हरियाणा रोडवेज़ की 211 विशेष बसें केवल स्कूल व कॉलेज की छात्राओं के लिए चलाई गईं।
- कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए PNDT Act तथा MTP Act का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 140 प्राथमिकी दर्ज।
- 'महिला एवं किशोरी सम्मान योजना' के तहत बी.पी.एल. परिवारों की 10 से 45 वर्ष तक की 22.50 लाख किशोरियों व महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित।
- 'मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना' के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आने वाले 6 वर्ष तक के 9 लाख से अधिक बच्चे तथा लगभग 3 लाख गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताएं लाभान्वित।
- 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' के तहत शहरी गरीब महिलाओं के रोज़गार के लिए 4257 स्वयं सहायता समूह बनाए गये।

स्वावलम्बन

कौशल से संवरता भविष्य
सक्षम युवा-सशक्त युवा

- गत 6 वर्षों में योग्यता के आधार पर लगभग 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी, जिनमें से एक वर्ष में दी गई लगभग 10,000 नौकरियां।
- युवाओं को विदेशों में रोजगार में मदद के लिए 'विदेश सहयोग विभाग' बनाया।

- रोज़गार मेलों के माध्यम से 42,941 बेरोज़गार युवाओं को मिला निजी क्षेत्र में रोज़गार। इसके अलावा ओला, ऊबर, जी4एस, जोमैटो एवं स्विगी के साथ अनुबन्ध-सहभागिता में 79,680 युवाओं को रोजगार दिया।
- 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' के तहत 68,770 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण।
- विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 71,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- निजी कम्पनियों के साथ मिलकर युवाओं को प्रशिक्षण देकर नौकरी के लिए तैयार करने की 'पहल योजना' के तहत 34 सरकारी कॉलेजों का निजी कम्पनियों के साथ समझौता।
- विद्यार्थियों को उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए 27 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने 71 ट्रेड्स में 40 उद्योगों के साथ MOU किया।
- National Skills Qualifications Framework के माध्यम से 1001 स्कूलों के बच्चों को विभिन्न कौशलों में निपुण बनाने की व्यवस्था का शुभारंभ।
- जिला सिरसा के गांव पन्नीवाला मोटा में हरियाणा का पहला 'मॉडल स्किल सेंटर' शुरू। इसमें विभिन्न ट्रेड्स में 240 बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए 'उद्योग मित्र योजना'।

सबका सम्मान – सबका उत्थान

- 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना' के तहत अब किसी भी राशन डिपो से अपना आधार कार्ड दिखाकर राशन लेने की सुविधा।

- हरियाणा में पहली बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मंहगाई के साथ जोड़ा गया और ये पेंशन मंहगाई दर से भी ज्यादा बढ़ाकर 2250 रुपये मासिक की, जो पहले 2000 रुपये थी।
- स्कूल न जा सकने वाले 18 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों की सहायता राशि 1400 रुपये से बढ़ाकर 1650 रुपये मासिक तथा निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता भी 1100 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये मासिक की।
- 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत 8 लाख 8 हज़ार 850 पंजीकृत परिवारों को 248.63 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता।
- निःशक्तजनों के कल्याण के लिए दूल्हा/दुल्हन में से यदि कोई एक निःशक्त है तो 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के अन्तर्गत उसे 31,000 रुपये व दोनों निःशक्त हैं तो 51,000 रुपये की शगुन राशि देने का प्रावधान।
- सामूहिक विवाह करने वाले दूल्हा/दुल्हन में से यदि कोई एक हरियाणा का निवासी है, तो उसे 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के अन्तर्गत 51,000 रुपये।

हर समस्या का निदान
कर्मचारियों का भी पूरा सम्मान

- 52 साल की उम्र से पहले कर्मचारी का निधन होने पर 'नई एक्स-ग्रेसिया स्कीम' के तहत उसके आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा आधार पर नौकरी।

- आश्रित को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये व मकान किराया भत्ता या सरकारी आवास की अनुमति की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष की।
- लापता सरकारी कर्मचारी के परिजन प्राथमिकी दर्ज होने के 6 महीने बाद अनुकम्पा लाभ के हकदार, पहले यह अवधि 7 वर्ष थी।
- कर्मचारियों को हार्ट और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा।
- आउटसोर्सिंग नीति के तहत महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश की सुविधा।
- 'ऑनलाइन ट्रांसफर नीति' 7 विभागों में लागू तथा 10 अन्य विभागों में होगी जल्द लागू।
- क्लास वन सरकारी अधिकारी से सीधा आई.ए.एस. बनने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान।
- कर्मचारियों को बायोमैट्रिक हाजिरी लगाने से छूट व घर से काम करने की सुविधा के साथ सेनिटाइजर और मास्क उपलब्ध करवाए।
- चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक सेवाओं में सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृति 31 मार्च, 2020 थी, की सेवाओं को एक्सटेंशन दी।
- अपनी ड्यूटी करते हुए दुर्भाग्यवश कोविड का शिकार हो जाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए एक्स-ग्रेसिया राशि बढ़ाकर की 30 लाख रुपये। नगरपालिका के कर्मचारियों का भी 10 लाख रुपये का बीमा।

ई-गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस

- सभी सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ घर पर ही देने, डुप्लीकेसी को समाप्त करने व नागरिकों का डाटाबेस तैयार करने के लिए 'परिवार पहचान-पत्र कार्यक्रम' का पोर्टल www.meraparivar.haryana.gov.in शुरू।
- इस पोर्टल से 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना', 'वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना', 'निःशक्त पेंशन योजना' तथा 'विधवा व निराश्रित महिला पेंशन योजना' को जोड़ा गया।

- इस पोर्टल पर अब तक 60.14 लाख परिवारों का रिकॉर्ड उपलब्ध, जिनमें से 15.03 लाख परिवारों के पहचान-पत्र बनकर तैयार।
- सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की देख-रेख एवं डिजिटल साधनों से सेवाओं व योजनाओं का लाभ देने के लिए 'नागरिक संसाधन सूचना विभाग' गठित।
- सरकारी कामकाज में तेजी लाने और फाइलों के ऑनलाइन शीघ्र निपटान के लिए 'ई-ऑफिस' की शुरुआत। इससे प्रदेश के 70 विभाग और 4 निगम जोड़े गए।
- वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आमजन की सरकार तक पहुंच के लिए 'ई-सचिवालय' पोर्टल का शुभारम्भ।
- 'वेब-हेलरिस' पूरे प्रदेश में लागू। इस पर सब सम्पत्तियों और भू-रिकॉर्ड का ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध। इसमें दस्तावेजों का पंजीकरण, इंतकाल, जमाबंदी रिकॉर्ड का रख-रखाव, ई-खसरा गिरदावरी, रोजनामचा व स्वामित्व रिकॉर्ड की नकल आदि जारी किये जाते हैं।
- 15,311 अटल सेवा केन्द्रों और 117 अंत्योदय सरल केन्द्रों के माध्यम से 39 विभागों की 542 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- सी.एम. विंडो पर प्राप्त 7,59,785 शिकायतों में से 7,25,248 शिकायतों का समाधान।
- प्रदेश में 4496 ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट सेवाओं के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाए गये।
- भ्रष्टाचार का अड्डा माने जाने वाले आर.टी.ए. कार्यालयों पर शिकंजा कसते हुए सभी जिलों में आर.टी.ए. सचिव के स्थान पर अलग से डी.टी.ओ. नियुक्त।
- वाणिज्यिक वाहनों की चैकिंग व पासिंग करने वाले वाहन निरीक्षक पर बॉडी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सारी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी और इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय पर की जाएगी।
- वाणिज्यिक वाहनों की ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए सड़कों पर पोर्टेबल धर्मकाँटे लगाए जाएंगे, जिससे वाहन चालक को भी पता नहीं लगेगा कि कब उसके वाहन का तोल हो चुका है।
- 45 पोर्टेबल धर्मकाँटे खरीद लिए गए हैं और इनकी सफलता के बाद पूरे प्रदेश में और भी पोर्टेबल धर्मकाँटे लगाए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्र की बदलती तस्वीर

- गांववासियों को उनकी सम्पत्ति का मालिकाना हक देने के लिए गांव सिरसी (करनाल) से 'लाल डोरा मुक्त योजना' शुरू, जिसे अब 'स्वामित्व योजना' के रूप में पूरे देश ने अपनाया। प्रदेश के 227 गांवों के 21,927 परिवारों को मिला सम्पत्ति का मालिकाना हक। तीन शहर-करनाल, जींद व सोहना भी लाल डोरा मुक्त।

- इससे ग्रामवासियों को ज़मीन की खरीद-फरोख्त व उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला। मालिकाना हक से सम्बन्धित विवादों पर भी लगेगा अंकुश।

- 'ग्राम दर्शन' पोर्टल का 2 अक्तूबर, 2020 को शुभारम्भ, जो पंचायतों का 'साइबर फेस' है। इस पर राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों का संपूर्ण डाटा, विकास परियोजनाओं और पंचायत द्वारा करवाए जाने वाले आवश्यक कार्यों की सूची उपलब्ध। यह ग्रामीणों के लिए अपनी समस्याएं व शिकायतें बताने का मंच भी है।

- विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को 2235.46 करोड़ रुपये की राशि जारी।

- प्रदेश के 114 गांव बने 'डिजिटल गांव'। अब एक क्लिक पर ग्रामीणों को सरकार की सैंकड़ों योजनाओं का मिलेगा लाभ।

- 'राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' के तहत 6403 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन, जिन पर कुल 67.71 करोड़ रुपये खर्च।

- 'दीन दयाल उपाध्याय योजना- ग्रामीण कौशल' के अन्तर्गत 35.77 करोड़ रुपये की राशि खर्च।

- गांव में शराब का ठेका खोलने अथवा न खोलने की शक्ति ग्राम सभा को दी। गांव के 10 प्रतिशत लोग ठेका न खोलने का प्रस्ताव करते हैं तो ठेका नहीं खोला जाता जिसके तहत 430 गांवों में शराब का ठेका न खोलने की मंजूरी।

- पंचायत चुनावों में महिलाओं हेतु आरक्षित 33 प्रतिशत सीटों के बदले 42 प्रतिशत महिला प्रत्याशी पंच व सरपंच चुनी गईं। अब हमारा लक्ष्य महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का है।

शहरों का कायाकल्प

- 'स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत फरीदाबाद में 1429 करोड़ रुपये की लागत से 41 परियोजनाओं पर तथा करनाल में 1172 करोड़ रुपये की लागत से 57 परियोजनाओं पर कार्य जारी।

- स्वच्छता सर्वेक्षण-2020, स्टेट रैंकिंग में हरियाणा छोटे राज्यों में दूसरे पायदान पर। इस रैंकिंग में 10 लाख की आबादी वाले शहरों में करनाल 17वें स्थान पर, रोहतक 35वें, फरीदाबाद 38वें और पंचकूला 56वें स्थान पर।

- उन शहरी नागरिकों को सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत एकमुश्त छूट, जिन्होंने वर्ष 2019-20 के अपने सभी देयकर/बकाया 31 जनवरी, 2020 तक चुका दिये। जिन्होंने वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक के अपने सम्पत्ति कर के देय/बकाया 31 जनवरी, 2020 तक चुका दिये, उन्हें सम्पत्ति कर के ब्याज की एकमुश्त छूट।

- सभी पालिकाओं को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी।

सबको आवास

- विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए 'सभी के लिए आवास' विभाग बनाया।

- 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत 6 वर्षों में 55,893 मकान बनाए गए, इनके अलावा 19,657 फ्लैट्स भी बनाए।
- हांसी में 532, पंचकूला में 44 ई.डब्लयू.एस. मकान अलॉट किये तथा बी.पी.एल. परिवारों के लिए 1200 मकान निर्माणाधीन।

बिजली का प्रसार-विकास का आधार

- 'म्हारा गांव-जगमग गांव योजना' के तहत प्रदेश के 70 प्रतिशत (4755) गांवों को 24 घंटे बिजली। 10 जिलों - पंचकूला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल व रेवाड़ी के सभी गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति।

- बिजली के लाइन लॉसिस 30.3 से घटकर 17.27 प्रतिशत रह गए।
- प्रदेश में 16,753 नये ट्रांसफॉर्मर लगाए तथा 1,29,280 नये कनेक्शन दिये।
- प्रदेश में 824 किलोमीटर लम्बी प्रसारण लाईनें जोड़ी गईं, जिन पर कुल 584.37 करोड़ रुपये खर्च।
- निर्बाध व उत्तम गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति के लिए 38 नए सब-स्टेशन स्थापित तथा 111 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की गई।
- वितरण नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए आगामी 5 वर्षों में अनुमानित 10,253 करोड़ रुपये की लागत की योजना बनाई।
- घरों, कॉलोनियों, तालाबों तथा स्कूलों के ऊपर से गुजरने वाली 2539 खतरनाक लाईनों की शिफ्टिंग का कार्य लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत से शुरू।

सौर ऊर्जा से बिजली की बचत

- 1696 करोड़ रुपये की लागत से 50,000 सोलर पंप लगाने की परियोजना शुरू। इस योजना के प्रथम चरण में 15,000 सोलर पंप लगाने की मंजूरी प्रदान, जिनमें से 1271 सोलर पंप लगाए गए।

- गांव मोरखी (जींद) में 14 करोड़ रुपये की लागत से राज्य का पहला ग्रिड से जुड़ा 1.2 मेगावाट क्षमता का बायोगैस आधारित पावर प्लांट चालू। इसमें प्रत्येक वर्ष 85 लाख यूनिट बिजली का होगा उत्पादन।
- बिजली से चलने वाले नलकूपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए ज़िला यमुनानगर के मारूपुर फीडर, (181 ट्यूबवैल) तथा ज़िला करनाल के बयाना फीडर (287 ट्यूबवैल) का चयन।
- छतों पर 48 मेगावाट क्षमता के तथा जमीन पर 38.10 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित।
- 330 गौशालाओं में 2 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए।
- गांवों में एल.ई.डी. आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम के तहत 1084 लाईटें लगवाईं।
- घरों में उपलब्ध इन्वर्टर चार्जर को सोलर पैनल से चार्ज करने के लिए 6,000 से 10,000 रुपये तक का अनुदान।
- फतेहाबाद एवं जींद में 49.8 मेगावाट क्षमता की पराली आधारित बायोमास परियोजनाएं स्वीकृत। कुरुक्षेत्र व कैथल में कार्य प्रगति पर।

प्रगति की रफ्तार- उद्योग व व्यापार

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'एम.एस.एम.ई. विभाग' का गठन।
- गत एक वर्ष में 2409.38 करोड़ रुपये के निवेश से 53 बड़े व मध्यम तथा 14,804 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगे। इनमें 97,623 लोगों को रोज़गार मिला।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य। अब तक 4 हज़ार से ज्यादा युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण, जो राजस्थान से 2 गुणा, पंजाब से 4 गुणा, उत्तराखण्ड से 5 गुणा तथा हिमाचल प्रदेश से 14 गुणा है।

- उद्यमों में लगे कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए 'हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम' पोर्टल शुरू।
- फ्लिपकार्ट समूह द्वारा मानेसर के पातली हाजीपुर में 140 एकड़ जमीन पर 3 मिलियन वर्ग फीट के कवर क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित करने का निर्णय।
- 'आउटरीच कार्यक्रम' के तहत 60 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश की सहमति जताई।
- उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों का संचालन पुनः शुरू करने के लिए **saralharyana.gov.in** पोर्टल पर अनुमति व पास दिए।
- विभागों, बोर्डों व निगमों और प्राधिकरणों की तरफ 15 मार्च, 2020 को और उसके बाद भी बकाया देय राशियों के भुगतान को 15 मई, 2020 तक स्थगित किया।
- मार्च, अप्रैल और मई महीने के लिए 40 हज़ार रुपये तक प्रति माह के फिक्स चार्ज वाले उपभोक्ताओं को 30 हज़ार रुपये की सीलिंग के साथ फिक्स चार्ज में छूट।
- 40 हज़ार रुपये से अधिक फिक्स चार्ज वाले उपभोक्ताओं को मार्च, अप्रैल और मई 2020 के बिलों में फिक्स चार्ज में 25 प्रतिशत की छूट।
- सरकारी, शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं की दुकानों व भवनों के किराये में 15 मार्च से 15 मई, 2020 तक दो महीने की छूट।
- एन-95 और 16 पी.पी.ई. किट बनाने वाले राज्य के दो एम.एस.एम.ई. निर्माताओं को भारत सरकार से अनुमति दिलवाई। इससे राज्य में 85,000 पी.पी.ई. किट और 40,000 एन-95 मास्क की दैनिक उत्पादन क्षमता बढ़ी।
- चीन से अपने विनिर्माण बेस को स्थानांतरित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्षमतावान निवेशकों के साथ वेबिनार के माध्यम से तीन-दिवसीय ओपन हाऊस का आयोजन किया गया।

व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं

- 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना, मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के मामले में पंजीकृत करदाताओं को 5 लाख रुपये का बीमा कवर।

- 'मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना' के तहत आग और सेंधमारी के मामले में पात्र करदाताओं को माल या फर्नीचर व फिक्स्चर या दोनों के नुकसान के लिए 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर।
- इन दोनों योजनाओं में पंजीकृत 3.75 लाख व्यापारियों के प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया गया। अब तक 61 लाख रुपये के क्लेम दिए गए।
- अप्रैल, 2020 से अब तक 300.54 करोड़ रुपये का वैट रिफण्ड किया।

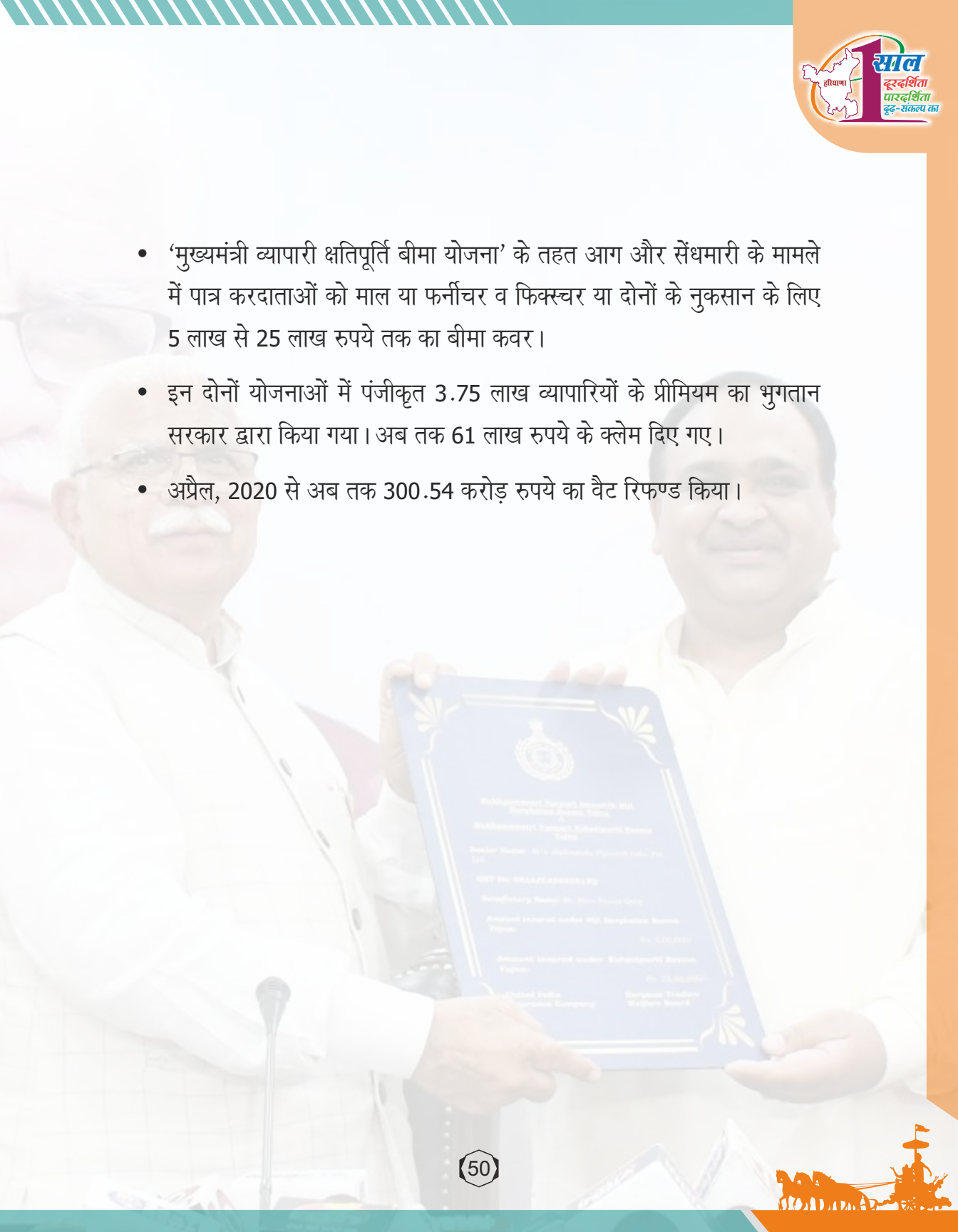

सड़क हुई सुदृढ़, रेल से मिली रफ्तार

- प्रदेश के लिए 1070 किलोमीटर लम्बे 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित, जिनमें से 669 किलोमीटर लम्बे 11 मार्गों पर काम शुरू। इससे हरियाणा का हर ज़िला जुड़ेगा राष्ट्रीय राजमार्ग से।
- भिवानी-खरक (एन.एच.709 ई.) सड़क, जिसमें भिवानी बाईपास भी शामिल है, का 4 लेन का कार्य 247.25 करोड़ रुपये की लागत से शुरू।

- कैथल-ढाण्ड सड़क, देवबन-राजौंद-असन्ध सड़क, कोंड-मूनक-सालवन-असन्ध सड़क, करनाल-काछवा-सांबली-कौल सड़क, नीलोखेड़ी-कारसा-ढांड सड़क तथा भिवानी-लोहारू सड़कों को 299.15 करोड़ रुपये की लागत से चौड़ा किया गया।
- 1719 करोड़ रुपये की लागत से 440 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें बनाईं तथा 3490 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया।
- 6 करम या इससे अधिक चौड़े सभी 530 कच्चे रास्तों को 1130 करोड़ रुपये की लागत से पक्की सड़क में बदलने का काम शुरू।
- करनाल-कैथल सड़क को 175 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन बनाने का कार्य शुरू।
- 140.84 करोड़ रुपये की लागत से पिंजौर बाईपास के निर्माण का काम शुरू।
- 1300 करोड़ रुपये की लागत से 52 रेलवे लाइन के पुलों के काम की शुरुआत।
- मेट्रो की तर्ज पर रोहतक-गोहाना रेलवे लाइन पर 300 करोड़ रुपये की लागत से बने देश के पहले 4.8 कि.मी लम्बे रेलवे एलिवेटिड ट्रैक का प्रारंभिक ट्रायल सफल।
- कुरुक्षेत्र शहर में 5 लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए एक एलिवेटेड रेलवे लाइन परियोजना पर काम शुरू।
- 844.15 करोड़ रुपये की लागत से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन का कार्य जारी।
- जींद-हांसी नई रेलवे लाइन (50 कि.मी.) और करनाल-यमुनानगर नई रेलवे लाइन (61 कि.मी.) बनाने का निर्णय।
- 5.50 हज़ार करोड़ रुपये के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी। पलवल से सोनीपत और सोहना से मानेसर की दूरी होगी कम।

सुरक्षित व सुगम सफर

- सुगम यातायात के लिए रोडवेज़ के बस बेड़े में 150 मिनी बसें तथा 18 सुपर लग्ज़री बसें शामिल। इसके अलावा, 'किलोमीटर स्कीम' के तहत 462 नई बसें भी शामिल।

- अग्रोहा (हिसार) बस अड्डे, पलवल बस अड्डे व वर्कशाप तथा अलेवा (जींद) बस अड्डे का निर्माण कार्य 14.95 करोड़ रुपये की लागत से पूरा।
- पी.पी.पी. मोड पर एन.आई.टी. फरीदाबाद बस टर्मिनल का विकास करने का काम शुरू।
- साधारण बसों में 41 विभिन्न श्रेणियों के लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधाएं। इनमें 25 नवम्बर, 2019 से कैंसर पीड़ित के एक सहयोगी को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी शामिल है।

हमारा ध्येय : हर घर पहुँचे स्वच्छ जल

- 'जल जीवन मिशन' के तहत 30 जून, 2022 तक शत-प्रतिशत घरों में नल से स्वच्छ जल आपूर्ति के लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11,85,127 जल कनेक्शन दिये।
- 'हरियाणा फ्रेश ब्रांड' नाम से मिनरल पानी का प्लांट स्थापित करने का निर्णय।

- 24.25 करोड़ रुपये की लागत से 17 नए जलघर स्थापित।
- पेयजल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 104.75 करोड़ रुपये की लागत से 404 नलकूप, 75 बूस्टिंग स्टेशन शुरू और 765.58 करोड़ रुपये की लागत से 4643 किलोमीटर लम्बी नई पाइप लाईनें बिछाई गईं।
- 10,000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति बढ़ाने तथा सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए 'महाग्राम योजना' के तहत 128 गांवों का चयन व 21 गांवों में काम शुरू।
- 49.60 करोड़ रुपये की लागत से 6 मल शोधन संयंत्र चालू तथा 6.40 करोड़ रुपये की लागत से एक संयंत्र निर्माणाधीन।
- 'जल बचाओ-कल बचाओ' अभियान के तहत 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स से 700 क्यूसिक ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का पावर प्लांट्स व उद्योगों में किया जा रहा उपयोग।
- ताजा जल संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले थर्मल पावर प्लांट्स में टावरों की कूलिंग के लिए ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का होगा उपयोग। इसके अलावा, प्रतिदिन 1000 किलो लीटर पानी का उपयोग करने वाले उद्योग के लिए भी ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग अनिवार्य।
- शहरों में पेयजल को छोड़कर अन्य उद्देश्यों जैसे कि बगीचों, बागवानी और पार्कों आदि की सिंचाई के लिए ट्रीटेड वेस्ट वाटर का उपयोग अनिवार्य।

कोविड–19 महामारी के दौरान राहत

- गरीबों की मदद के लिए 1200 करोड़ रुपये का पैकेज।
- 16 लाख 20 हज़ार परिवारों के खातों में 619 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता।
- 27,01,077 परिवारों को तीन महीनों के लिए 154 करोड़ रुपये का मुफ्त राशन दिया।

- लॉकडाउन के दौरान मज़दूरों व गरीबों के लिए बनाये गये 585 राहत शिविरों में 91,200 मज़दूरों के लिए रहने, खाने व चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की गई।
- 'ऑपरेशन संवेदना' के तहत 4.44 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को 100 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों व 6629 बसों के माध्यम से सरकार के खर्चे पर उनके गृह राज्यों में पहुंचाया गया।
- राशन कार्ड रहित लगभग 5 लाख जरूरतमंद परिवारों को Distress Ration Token के जरिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति गेहूं तथा एक किलो दाल प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त दिया गया।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले साढ़े 4 लाख से अधिक परिवारों को हर हफ्ते 1000 रुपये की दर से 200 करोड़ रुपये से भी अधिक की आर्थिक सहायता दी गई।
- लगभग साढ़े 4 लाख मज़दूरों को लॉकडाउन के दौरान 1000 रुपये प्रति सप्ताह की दर से 200 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
- 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना' के तहत 80 लाख कार्य दिवसों का सृजन कर लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि श्रमिकों के खातों में पहुँचाई।
- वर्ष 2020-21 के मनरेगा श्रमिकों के लिए 550 करोड़ रुपये मंजूर, जिसमें से 133 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी।
- मिड-डे मील के बदले 14.34 लाख विद्यार्थियों को घर पर ही राशन दिया।
- 25,960 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 10 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को मुफ्त राशन।
- 3 लाख गरीबों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 15 हज़ार रुपये तक ऋण केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर।

इलाज के लिए प्रबन्ध

- 11 सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में कोरोना वार्ड तथा 40 अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया।
- चिकित्सा मदद व कोरोना सम्बन्धी जानकारी देने के लिए राज्य व जिला स्तर पर हेल्पलाइन नम्बर बनाए।
- राज्य में अब तक लगभग 25 लाख कोरोना के टेस्ट करवाए गए।

- गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, पंचकूला व करनाल में प्लाज़्मा बैंक खोले।
- राज्य सरकार ने सभी निजी अस्पतालों के लिए इलाज के खर्च की अधिकतम सीमा तय की है।
- पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए 954 नए डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त तथा चिकित्सा और पैरा-मेडिकल स्टाफ को एक्सटेंशन।
- डॉक्टरों के लिए एक्स-ग्रेसिया राशि 50 लाख रुपये, नर्सों के लिए 30 लाख रुपये तथा अन्य कर्मचारी के लिए 20 लाख रुपये। निजी अस्पतालों के स्टाफ को भी एक्स-ग्रेसिया।
- सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी पर रहते हुये कोरोना से मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की एक्स-ग्रेसिया अनुदान राशि का प्रावधान।
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 197 पदों पर 70 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त डॉक्टरों को अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की स्वीकृति।
- कोविड-19 से सम्बंधित सभी जानकरियों के लिए 'हरियाणा सहायक' नामक Mobile App Launch किया। इसके अलावा 95 से अधिक मोबाइल हेल्थ टीमों का गठन किया गया।

कोरोना की होगी हार

जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

जागरूक रहें – ज़िम्मेदार बनें

महानिदेशक – सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित एवं संवाद सोसाइटी के माध्यम से मुद्रित (वर्ष-2020)